standards and norms, staffing patterns etc. Any resultant economy arising out of individual studies, is to be effected by the concerned Ministries/Departments. No central monitoring is done in this regard by the Ministry of Finance.

(d) to (f). Keeping the Government expenditure under control is a continuous exercise. Instructions are issued in this regard from time to time. These instructions include reduction in posts, in expenditure on petrol/diesel, telephones etc.

Cut in military expenditure

3321. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the World Bank has asked both India and Pakistan to cut military expenditure;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the response of Indian Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY) :

(a) No, Sir.

(b)and (c). Do not arise

जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं हेतु ऋण दिया जाना

3322. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कई जिलों की जलपूर्ति और मल-निकासी की योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण की राशि इस संबंध में विद्यमान मानदण्डों के अनुसार ऐसी योजनाओं की स्वीकृत कुल लागत के 50 प्रतिशत से भी कम है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा योजनाओं की लागत में वृद्धि होने पर कोई ऋण नहीं दिया जाता ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 20,000 व्यक्तियों से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में पेय जल और निकासी की योजनाओं की स्वीकृत लागत का 70 प्रतिशत भाग समान रूप से ऋण के रूप में दिया जाएगा तथा क्या निगम द्वारा इन योजनाओं की संशोधित लागत के लिए और ऋण स्वीकृत किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) . (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचना दी है कि वे योजना आयोग द्वारा किए गए आवंटन के आधार पर जलपूर्ति और मलव्ययन बोर्डों नगर पालिकाओं/राज्य सरकारों जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, को जल आपूर्ति और मलव्ययन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष ऋण प्रदान करते हैं। जल आपूर्ति और मलव्ययन योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का वर्तमान ढांचा इस प्रकार है :—

वित्त पोषण का ढांचा

योजना की लागत	वर्तमान ढांचा	
	शहरी	ग्रामीण
(1)	(2)	(3)
जहां लागत 1,00 करोड़ रुपये से अधिक न हो।	लागत का 2/3 भाग	लागत का 50 प्रतिशत